



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 104-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 9, 2023 (JYAISTHA 19, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जून, 2023

संख्या 19/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 59/2023.— हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 55/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 9/2022, दिनांक 6 सितम्बर, 2022 के प्रतिनिर्देश से, मैं, अशोक कुमार मीना, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।
(2) ये जून, 2023, के बारहवें दिन से लागू होंगे।
- हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,—
 - खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - प्ररूप अनु0-1 में अनुज्ञप्ति के लिए,—
 - ₹1,65,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख प्रूफ लीटर से कम या बराबर है;
 - ₹2,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोट 10 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 25 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;
 - ₹2,25,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;
 - ₹3,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि प्रत्येक अनु0-1 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस के 30 प्रतिशत के बराबर वापसीयोग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन किसी भी राशि या शास्ति के लिए जब्त या समायोजित होने के लिए उत्तरदायी होगी:

परन्तु यह और कि यदि अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से बचने के लिए मदिरा की कोई अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी की तरफ शास्ति आदि के कारण देय राशि की वसूली उसके द्वारा अपने खुदरा ठेके (अनु0-2) अनुज्ञप्ति की जमा की

गई प्रतिभूति से भी की जाएगी और किसी अनु0-1 गोदाम के स्टॉक में कमी के मामले में 15,000 से अधिक पुफ लीटर और 30,000 पुफ लीटर तक न्यूनतम शास्ति जो उल्लंघन के लिए लगायी जा सकती है, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 1.5 गुना से कम नहीं होगी। यदि किसी अनु0-1 गोदाम के स्टॉक में 30,000 पुफ लीटर से अधिक की कमी पाई जाती है, तो उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 2 गुना से कम नहीं होगी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, शेष अन्य सभी प्रकार की मदिरा पर 0.5 प्रतिशत और बीयर पर 1 प्रतिशत टूट-फुट की छूट की अनुमति दी जायेगी। टूट-फुट के स्टॉक के सम्बन्ध में लगाई गई आबकारी शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जायेगा।”;

(ii) खण्ड (i-खख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-ख ख) प्ररूप अनु0-4/अनु0-5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:-

(क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को ₹ 25,00,000
प्रदान की गई अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति:

परन्तु गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2031 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर होटल तथा रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे स्थानों के लिए भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर-क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर-क्षेत्र, रोहतक, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क मानेसर, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, पंचकूला इत्यादि। औद्योगिक शहरों धारुहेड़ा और बहादुरगढ़ में प्रतिष्ठित रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। मोरनी उप-तहसील क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित होटलों और रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति भी प्रदान की जाएगी:

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात-दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएंगी। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटर्स में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारी एक या अधिक अतिरिक्त स्थलों को उप-पट्टे पर देना चाहता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से 10 लाख रुपये प्रत्येक अतिरिक्त स्थल के लिए निर्धारित फीस प्रभारित की जाएगी। अनु0-4/अनु0-5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹20,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त स्थल अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात-दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटर्स में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी अवस्थित किसी होटल को भी अनन्तिम रूप से अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी इस शर्त के अधीन कि आवेदक ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले एक वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 3 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अनन्तिम अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्ति अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल के लिए,-

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुज्ञप्ति फीस
1	गुरुग्राम	₹18,00,000
2	फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत	₹14,00,000
3	सभी अन्य जिले	₹10,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, एक अतिरिक्त स्थल तथा कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति वाले होटल अन्य

खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति राज्य के किसी भी स्थान पर अवस्थित तीन सितारा और सितारा होटलों की उपर की श्रेणियों को भी दिया जायेगा। राज्य में पर्यटन/साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रिसोर्ट और रेस्तरां आदि को अनु0-4/अनु0-5 के रूप में बार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का मामला, जिसमें अच्छी अवसंरचना और सुविधाएं हैं, लेकिन आबकारी नीति के सम्बन्धित खंडों में वर्णित भौगोलिक प्रतिबन्ध से बाहर स्थित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे सभी मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अपनी सिफारिश सहित सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

राज्य में कहीं भी स्थित विद्यमान कार्यात्मक बारों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा कलेक्टर की ओर से किया जायेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को उसकी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त फीस के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, आयोजनों तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन शुल्क और परमिट शुल्क के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा खरीदेगा। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
व्हिस्की	₹55 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹45 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹35 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(घ) प्ररूप अनु04/अनु0-5 में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- | | | |
|-------|---|-----------------------------|
| (i) | जिला गुरुग्राम के लिए | ₹16,00,000 |
| (ii) | जिला फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत के लिए | ₹12,00,000 |
| (iii) | गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत के सिवाए राज्य में सभी अन्य जिलों के लिए | ₹8,00,000 |
| (iv) | सभी जिलों में हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए | ₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस |
| (v) | सभी जिलों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार | ₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस: |

परन्तु ₹6.00 लाख की प्रशमन प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्रशमन अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि कोई भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी, वाईन/बीयर/आरटीबी/साईडर/लिक्योर के सिवाय जाम की बजाय बोतलों में मदिरा की बिक्री या बेहिसाब मदिरा की बिक्री या होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों के बिना मदिरा की बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति रखने के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है।

टिप्पण 1. पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पण 2. हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रुपये के बराबर फीस के भुगतान पर चलाने की अनुमति दी जाएगी।”;

(iii) खण्ड (ii-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii-ग) भारत में बनी विदेशी स्पिरिट तथा बीयर पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:-

		राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए	भारत के भीतर राज्य से बाहर आपूर्ति के लिए	भारत के बाहर निर्यात
(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी-2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹14.00/- प्रति पूफ लीटर	₹4.50/-प्रति पूफ लीटर	शून्य
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए	₹18.00/- प्रति पूफ लीटर	₹7.00/-प्रति पूफ लीटर	शून्य
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिंग के लिए तथा जहाँ फ्रेंचाईज फीस उदगृहीत नहीं की गई है	₹22.00/- प्रति पूफ लीटर	₹7.50/-प्रति पूफ लीटर	शून्य
(घ)	बुअरज के द्वारा बीयर की बाटलिंग के लिए	₹11.00/- प्रति बल्क लीटर	₹1.00/-प्रति बल्क लीटर	शून्य:

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उदगृहणीय होगी, यदि कोई भी फ्रेंचाईज फीस उदगृहीत नहीं की गई है।”;

(iv) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परन्तु प्ररूप अनु0-12 क में अस्थायी अनुज्ञप्ति संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन के दौरान शराब परोसने के लिए कब्जा सीमा से अधिक के लिए दी जायेगी। किसी भी व्यक्तिगत समारोह, मिलन समारोह या विवाह समारोह आदि की मेजबानी के लिए निम्नलिखित स्थानों के लिए अनु0-12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा:-

- बैंकट हाल, होटलों, क्लबों, रेस्तरां, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक पार्कों/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्थलों और धर्मशालाओं में शराब परोसने के लिए;
- किसी विशिष्ट दिन पर अस्थायी आधार पर अपने अनुज्ञप्त परिसरों के बाहर शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्त होटलों, रेस्टोरेंटों तथा क्लबों के लिए;
- कोई अन्य निजी स्थान।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे बैंकट हाल, पार्टी हॉल/लॉन वाले होटलों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में आबकारी विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। पार्टी हॉल/लॉन वाले बैंकट हॉल और होटलों का वार्षिक पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार होगा:-

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल की अवस्थिति	वार्षिक पंजीकरण फीस
1	महानगर विकास प्राधिकरणों जैसे जी0एम0डी0ए0, एफ0एम0डी0ए0 और पी0एम0डी0ए0 आदि की सीमाओं के भीतर	₹1,00,000
2	अम्बाला, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर की नगर निगमों सीमाओं के भीतर	₹50,000
3	अन्य नगर परिषद्/समिति सीमा	₹25,000

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल की अवस्थिति	वार्षिक पंजीकरण फीस
4	जिले की नगरपालिका सीमा के बाहर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर पडने वाले बैंकट हाल/होटल (आबकारी नीति तथा आबकारी नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन)	₹25,000
5	ग्रामीण क्षेत्रों में पडने वाले बैंकट हॉल(उपरोक्त श्रेणी में विनिर्दिष्ट से भिन्न)	₹10,000

अनु0-12क अनुज्ञप्ति के लिए फीस ढांचा निम्नानुसार होगा:-

(i)	वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्ति के लिए	₹5.000 प्रतिदिन प्रति समारोह
(ii)	निजी स्थान पर कब्जा सीमा से बाहर मदिरा परोसने के लिए व्यक्तिगत हेतु	₹1,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

प्ररूप अनु0-12क अनुज्ञप्ति में किसी भी क्लब, होटल या रेस्तरां के अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में अस्थायी अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी। सभी वाणिज्यिक स्थलों पर अनु0-12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन में, कैटरर का नाम और जी.एस.टी.ईन, जैसे विवरण, मेहमानों की अनुमानित संख्या और परोसी जाने वाली मदिरा की मात्रा शामिल होंगे:

परन्तु यह और कि यदि, किसी भी बैंकट हॉल/होटल इत्यादि वैध अनु0-12क अनुज्ञप्ति के बिना मदिरा परोसी जाती है, तो ऐसे बैंकट हॉल या होटल के मालिक/प्रबंधन/प्राधिकृत व्यक्ति के खिलाफ प्रथम अपराध के लिए ₹50,000/-, द्वितीय अपराध के लिए ₹1,00,000/- और तृतीय अपराध के लिए ₹1,50,000/-की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। आगे पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे बैंकट हाल या होटल को एक वर्ष की अवधि के लिए कोई भी आबकारी अनुज्ञप्ति/परमिट प्रदान करने के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा।”;

प्ररूप अनु0-12कक में अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए,- अनु0-12कक अनुज्ञप्ति मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक शो, मेगा शो, सेलिब्रिटी कार्यक्रमों और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों जैसे इवेंट के दौरान मदिरा परोसने के लिए कार्यक्रम आयोजकों सहित किसी भी व्यक्ति को नीचे दर्शायी गई आवेदन फीस के भुगतान पर दी जायेगी,

ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	प्रति दिन प्रत्येक आयोजन हेतु आवेदन फीस (₹ में)
5000 तक	₹50,000/-
5001 से 25000	₹2,50,000/-
25001 या उपर	₹10,00,000/-

यह अनुज्ञप्ति एक बार में अधिकतम तीन दिनों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा प्रदान किया जाएगा। आवेदन फीस के अतिरिक्त आवेदक को ऐसी मदिरा पर यथालागू आबकारी शुल्क, मूल्यांकन फीस, वैट और अन्य सरकारी उदग्रहण अग्रिम में जमा करना अपेक्षित होगा।

अनु0-12कक अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा और बीयर पर निम्नलिखित दरों पर निर्धारण फीस का भुगतान करेगा:-

मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस की दर
भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल रूप में बोतलबन्द)(बी0आई0ओ0)	₹450/- प्रति प्रूफ लीटर
बीयर/पीने के लिए तैयार पेय (आर0टी0बी0) तथा कोई अन्य श्रेणी	₹300/- प्रति बल्क लीटर

अनु0-12कक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यथालागू दरों पर वैट देय होगा।

(v) खण्ड (iv-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ख) प्ररूप अनु0-12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

वर्ग	अनुज्ञप्ति का प्रकार	जिला	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस	अतिरिक्त स्थल (गणना/अनुज्ञप्ति फीस)
(i)	एक प्रतिष्ठित क्लब को प्रदान किया गया अनु0-12ग	महानगर विकास प्राधिकरण वाले जिलों के लिए	₹20,00,000 /-	3 स्टार रेटिंग वाले अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति पर लागू उपबंधों के अनुसार
		अन्य जिलों के लिए	₹10,00,000 /-	
(ii)	एक आवासीय सहस्वामित्व को प्रदान किया गया अनु0-12ग	गुरुग्राम	₹15,00,000 /-	बिना स्टार रेटिंग वाले अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति पर लागू उपबंधों के अनुसार
		फरीदाबाद	₹12,00,000 /-	
		सभी अन्य जिलें	₹8,00,000 /-	

परन्तु अनु0-12ग अनुज्ञप्ति, राज्य में कहीं भी स्थित प्रतिष्ठित क्लबों को प्रदान की जाएगी। अनु0-12ग अनुज्ञप्ति, राज्य में कहीं भी स्थित आवासीय सहस्वामित्व में भी प्रदान की जाएगी। यह इस शर्त के अधीन होगी कि केवल सहस्वामित्व के निवासी या उनके मेहमान अनु0-12ग अनुज्ञप्ति वाले क्लब में सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात होंगे:

परन्तु यह और कि किसी भी सेना प्रायोजित क्लब जैसे सरहिन्द क्लब, अम्बाला को अनु0-12ग अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने पर, सेना के कर्मचारियों को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करना अनुज्ञात किया जाएगा जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली मदिरा के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे क्लब के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹5 लाख प्रति वर्ष होगी।

परन्तु यह और कि यदि कोई भी अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारी, जाम की बजाय बोतलों में मदिरा की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, वाईन/बीयर/आरटीबी/साईडर/लिक्योर के सिवाय या बेहिसाब शराब की बिक्री या होलोग्राम/आबकारी चिपकाने वाला लेबलों के बिना शराब की बिक्री तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो साल की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जायेगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है।

अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
व्हिस्की	₹55 प्रति प्रूफ लिटर	₹25 प्रति प्रूफ लिटर
वाईन	₹45 प्रति बल्क लिटर	₹25 प्रति बल्क लिटर
बीयर	₹35 प्रति बल्क लिटर	₹10 प्रति बल्क लिटर

अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। अनु0-12ग के माध्यम से आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि पाँच लाख रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।

टिप्पण:- पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।”;

(vi) खण्ड (iv-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ग) प्ररूप अनु0-12गग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

(क)	9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (दो विक्रय स्थलों सहित)	₹30,00,000
(ख)	18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (तीन विक्रय स्थलों सहित)	₹50,00,000:

परन्तु मदिरा परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार की बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु0-12गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। अनु0-12गग क्लब बार अनुज्ञप्तिधारियों को ₹10 लाख प्रति अतिरिक्त स्थल के बराबर शुल्क के भुगतान पर दो और अतिरिक्त स्थल खोलने की अनुमति होगी। अनु012-गग के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

अनु0-12गग अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन फीस और परमिट फीस के भुगतान के अध्यक्षीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा की किस्म	निर्धारण फीस	परमिट फीस
व्हिस्की	₹55 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹45 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹35 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

परन्तु यह और कि यदि कोई भी अनु0-12गग अनुज्ञप्तिधारी, वाईन/बीयर/आरटीबी/साईडर/लिक्योर के सिवाय जाम की बजाय बोतलों में मदिरा की बिक्री या बेहिसाब मदिरा की बिक्री या होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों के बिना मदिरा की बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो साल की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जायेगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12गग क्लब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(vii) खण्ड (v) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i) देशी मदिरा (अनु0-13) के थोक ठेके के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित अनुसार होगी:-

- (1) ₹60.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।
- (2) ₹75.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक या 50 लाख प्रूफ लीटर से कम है।
- (3) ₹100.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे अधिक है:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक प्रत्येक अनु0-13 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन किसी भी राशि या जुर्माना के लिए जब्त या समायोजित होने के लिए उत्तरदायी होगी:

परन्तु यह और कि यदि अनु0-13 अनुज्ञप्तिधारी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से बचने के लिए मदिरा की अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे अनु0-13 अनुज्ञप्तिधारी की तरफ शास्ति आदि के कारण देय होने वाली राशि की वसूली, उसके द्वारा अपने खुदरा ठेके (अनु0-14ए) अनुज्ञप्ति के लिए जमा की गई प्रतिभूति से की जाएगी और किसी अनु0-13 गोदाम के स्टॉक में कमी के मामले में, 10,000 प्रूफ लीटर से अधिक और 20,000 प्रूफ लीटर तक, न्यूनतम शास्ति, जो उल्लंघन के लिए लगाई जा सकती है, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के 1.5 गुना से कम नहीं होगी। यदि किसी अनु0-13 गोदाम के स्टॉक में 20,000 प्रूफ लीटर से अधिक की कमी पाई जाती है, तो उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के 2 गुना से कम नहीं होगी। मैट्रो सहित देशी मदिरा पर 0.5 प्रतिशत टूट-फुट की छूट की अनुमति दी जायेगी। टूट-फुट के स्टॉक के सम्बन्ध में अधिरोपित आबकारी शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जायेगा।”;

(viii) खण्ड (i-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-ग) प्ररूप अनु0-1कख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है	₹40,00,000
2.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹60,00,000
3.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 100 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹110,00,000
4.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है	₹150,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2023-24 में अनु0-1कख अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”;		

(ix) खण्ड (i-गग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-गग) प्ररूप अनु0-1कख1 में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 50 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹50,00,000
2.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 50 लाख बल्क लीटर से अधिक और 100 लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹100,00,000
3.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 100 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹150,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2023-24 में अनु0-1कख1 अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”;		

(x) खण्ड (i-ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-ड) प्ररूप अनु0-1ख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है	₹30,00,000
2.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹70,00,000
3.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 100 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹125,00,000
4.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 250 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹175,00,000
5.	यदि नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 250 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है	₹400,00,000
जैसे ही नीति वर्ष 2023-24 में अनु0-1ख अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”;		

- (xi) खण्ड (i-डड) में, उप-खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) प्ररूप अनु0-1ख-1 में अनुज्ञप्ति के लिए (बीयर के लिए),-

(I) नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ अनु0-1ख-1 द्वारा बीयर की वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) 50 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹35,00,000
(II) यदि अनु0-1ख-1 द्वारा बीयर की वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2022-23 (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक), 50 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹125,00,000

परन्तु जैसे ही नीति वर्ष 2023-24 में अनु0-1ख-1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बीयर की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, उपरोक्त श्रेणियों में यथाविहित, अनुज्ञप्तिधारी को, अगली उच्च श्रेणी में यथालागू अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।

“(ख) प्ररूप अनु0-1ख-1 में अनुज्ञप्ति के लिए (वाईन के लिए) ₹25,00,000;”।

- (xii) खण्ड (i-डडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i- डडड) प्ररूप अनु01-ख1-क (पीने के लिए तैयार पेय) में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2022-23 में (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) 1 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹10,00,000
2.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2022-23 में (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) 1 लाख बल्क लीटर से अधिक और 4 लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹20,00,000
3.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2022-23 में (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) 4 लाख बल्क लीटर से अधिक और 8 लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹50,00,000
4.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2022-23 में (अर्थात् 12.06.2022 से 11.06.2023 तक) 8 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹100,00,000

जैसे ही नीति वर्ष 2023-24 में अनु01-ख1-क अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, उपरोक्त श्रेणियों में यथाविहित, अनुज्ञप्तिधारी को, अगली उच्च श्रेणी में यथालागू अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी।”

- (xiii) खण्ड (i-डडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i-डडडड) प्ररूप अनु0-1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

(क) अनु0-1खच के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस ₹4,00,00,000/- होगी;

(ख) विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी;

(ग) यदि, पहले दौर में प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या सोलह (16) से अधिक या उसके बराबर है, अनु0-1खच अनुज्ञप्ति सभी पात्र आवेदकों को दिया जाएगा। ऐसे मामले में, विभाग राज्य में अनु0-1खच के आवंटन के लिए कोई और दौर (दौरे) शुरू नहीं करेगा:

परन्तु, यदि पहले दौर में प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या सोलह (16) से कम है, तो विभाग शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्तियों के आवंटन के लिए और दौर (दौरे) शुरू करेगा। शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्तियों की संख्या की गणना सोलह (16) से पिछले सभी दौर(रों) में आवंटित अनु0-1खच की संख्या घटाकर की जा सकती है:

परन्तु यह और कि यदि दूसरे या किसी बाद के दौर में पात्र आवेदनों की संख्या उस विशेष दौर में आवंटन के लिए उपलब्ध अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों की शेष संख्या से अधिक हो जाती है, तो ऐसे शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्तियों को उस विशेष दौर के पात्र आवेदकों के बीच ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(घ) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक, हरियाणा राज्य या किसी अन्य राज्य में कोई थोक अनुज्ञप्तिधारी, या कोई स्वत्वधारी फर्म या कोई भागीदारी फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या सुसंगत विधि के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत कोई फर्म होगी।

- (इ) आवेदक ₹2,00,000 की आवेदन फीस जमा करेगा। आवेदन फीस गैर वापसीयोग्य और गैर समायोज्य होगी। आवेदन के साथ ₹25,00,000 की अग्रिम राशि भी होगी। आवेदन, आवेदक की पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ होगा। सभी व्यक्तियों के पहचान प्रमाण, जैसे स्वत्वधारी, सभी भागीदार, निदेशक और प्राधिकृत व्यक्ति, यदि कोई भी ऐसा प्राधिकृत है, तो आवेदन के साथ ही ऑन-लाईन अपलोड किया जाना चाहिए।
- (च) सभी आवेदन, जो आबकारी विधि के उपबन्धों के अनुसार सही पाए गए हैं, को पात्र माना जाएगा। विभाग अपनी विभागीय वेबसाइट पर पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित करेगा और इसे उसकी अनुज्ञप्ति के आबंटन की तिथि माना जाएगा। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के प्रदान करने के दिन या 12 जून, 2023, जो भी बाद में हो, से वैध होगी।
- (छ) पात्र आवेदक अनुज्ञप्ति फीस के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि आबंटन की तिथि के एक सप्ताह के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विहित किया जाए जमा करवाएगा। अग्रिम राशि, प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए समायोज्य होगी। अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान के समय, अपने मदिरा गोदाम की भंडारण क्षमता की घोषणा करना भी आवश्यक होगी।
- (ज) निम्नलिखित मामलों में आवेदक की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी:—
- यदि वह निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहता है, या
 - यदि कोई सफल आवेदक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है, या
 - यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने अपने आवेदन में कोई गलत जानकारी या जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, या
 - यदि वह किसी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है, या
 - किन्हीं अन्य कारणों के लिए जिसे आबकारी आयुक्त उचित समझे।
- (झ) पात्र आवेदक अन्य सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, जो सार्वजनिक नोटिस, समय-समय पर जारी निर्देशों, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हों।
- (ण) आवेदक को अपनी प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद वह अनुज्ञप्तिधारी माना जायेगा।
- (ट) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति फीस के दस प्रतिशत के बराबर आठ मासिक किस्तों में अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा। आठ किस्तों में से पहली किस्त का भुगतान आबंटन के कैलेंडर माह के अन्तिम दिवस तक किया जाएगा। शेष सात किस्तों का भुगतान प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक किया जायेगा, आबंटन के महीने से आगामी महीने से शुरू होकर, जब तक सभी सात किस्त प्राप्त नहीं हो जाती।

यदि, अनुज्ञप्ति 2023 के सितम्बर महीने के बाद दी जाती है, तो अनुज्ञप्ति फीस का 80 प्रतिशत को मासिक किस्तों में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि पूरी राशि 15 अप्रैल, 2024 तक प्राप्त हो जाए। आबंटन के कैलेंडर माह के अन्तिम दिवस तक किस्तों का भुगतान किया जाएगा और शेष मासिक किस्त का भुगतान आबंटन के महीने से आगामी प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक किया जाएगा। अनुज्ञप्ति फीस का शेष भाग, पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति राशि से समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति से बकाया राशि, यदि कोई है, अनुज्ञप्तिधारी की ओर देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

भारत में बनी विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा करवाने में विलम्ब अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा।

- (ठ) प्रत्येक अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी के लिए न्यूनतम कोटा 75000 पेटियाँ होगी। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी के लिए कोटा उठाने की सूची निम्नानुसार होगी:—
- तिमाही—1 वार्षिक कोटा का न्यूनतम 25 प्रतिशत
 - तिमाही—2 वार्षिक कोटा का न्यूनतम 50 प्रतिशत
 - तिमाही—3 वार्षिक कोटा का न्यूनतम 75 प्रतिशत
 - तिमाही—4 वार्षिक कोटा का न्यूनतम 100 प्रतिशत

परन्तु नीति वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के मामले में, तिमाही-वार कोटा की गणना दिनों की संख्या के आधार पर समान रूप से विभाजित की जाएगी:

परन्तु यह और कि नीति वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी को कोटे की न्यूनतम मात्रा उठानी होगी। न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता की दशा में, प्रत्येक पेटी पर ₹1800 की शास्ति लगाई जायेगी। प्रत्येक गणना किए हुए तिमाही के अन्त में उठाए गए कोटा की कम मात्रा के लिए शास्ति लगाई जाएगी। तथापि, किसी तिमाही में कोटे की कमी के मामले में, शास्ति लगाई गई है, तो कोटा की उसी कमी के सम्बन्ध में किसी भी अनुवर्ती तिमाही में फिर से शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

(ढ) मूल्यांकन फीस तथा परमिट फीस निम्न प्रकार से उद्गृहीत की जायेगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

- (ड) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) पर वैट 3 प्रतिशत के साथ 5 प्रतिशत अधिभार की दर से प्रभारित किया जायेगा।
- (ण) किसी भी लागू विधि के उल्लंघन या आबकारी नियमों के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए लेबल रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी प्रकार की आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) ब्राण्डों के पंजीकरण के लिए ₹15,000/- की फीस प्रभारित की जाएगी।
- (त) ₹3,000 प्रति बोतल की शास्ति, शामिल बोतलों के आकार को ध्यान में रखे बिना, अनु0-1खच के परिसरों, या अनु0-1, अनु0-2, अनु0-2खच, अनु0-4 तथा अनु0-5, अनु0-12ग, अनु-12छ, अनु0-10ख, अनु0-10ड़ इत्यादि जैसे किसी अन्य परिसरों पर पाई गई विस्की और वाईन की हर बेहिसाब बोतल पर लगाई जाएगी। शास्ति उन अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाई जायेगी, जिसके परिसर पर शराब पाई गई है। बीयर के मामले में, शास्ति ₹1,500 प्रति बोतल, बोतल के आकार को ध्यान में रखे बिना लगाई जायेगी।
- (थ) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की विस्की और वाईन के स्टॉक पर, ₹2,000 प्रति बोतल की शास्ति, किसी भी अनुज्ञप्त परिसर पर कम पाये जाने पर, लगाई जाएगी। बीयर के मामले में, प्रति बोतल ₹1,000 की शास्ति लगाई जायेगी।
- (द) अनु0-1खच अनुज्ञप्ति किसी ऐसे स्थल पर स्थित नहीं होगा, जो किसी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से 5 किलोमीटर से कम हो।

वैध आयात निर्यात प्रमाणपत्र (आईसीसी) रखने वाला कोई भी व्यक्ति और जो (क) राज्य में स्थित कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस में सीधे आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) आयात करने; या (ख) राज्य के बाहर किसी अन्य कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की खेप को राज्य में अपने स्वयं के कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस में प्राप्त करने; या (ग) राज्य में अपने स्वयं के कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से राज्य के भीतर या बाहर स्थित किसी अन्य कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस को आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की खेप भेजने; या (घ) राज्य के भीतर या बाहर स्थित अपने कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी को आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की खेप आपूर्ति करने, की इच्छा रखता है, तो विभाग के साथ ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा। ऐसे व्यक्ति को, 25000 रुपये के पंजीकरण शुल्क के साथ विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य में स्थित किसी भी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की राज्य के अन्दर या राज्य से बाहर आपूर्ति करने वाले को (हरियाणा में और बाहर के लिए) मदिरा की सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की मासिक जानकारी विभाग द्वारा, यथाविहित रीति और प्ररूप में, प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य से बाहर स्थित किसी भी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी शराब (बी0आई0ओ0) की हरियाणा राज्य के अन्दर आपूर्ति करने वाले को विभाग द्वारा, यथाविहित रीति और प्ररूप में, हरियाणा के अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसी आपूर्ति की मासिक जानकारी जमा करनी अपेक्षित होगी। अनुपालना न करने की दशा में, ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से आपूर्ति रोक दी जायेगी।

ऐसे कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से जारी आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की सभी खेपों के साथ बीजक की एक प्रति, कस्टम प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट, कस्टम अधिकारियों द्वारा जारी पास और आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली घोषणा संलग्न होनी चाहिए।

- (ध) वर्ष 2022-2023 के लिए अनु0-1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी नीति वर्ष 2023-2024 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 11.06.2023 को आयातित विदेशी मदिरा का बचा हुआ स्टॉक अन्तरित कर सकता है। विस्की, स्कोच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी इत्यादि के लिए ₹75 प्रति प्रूफ लीटर की दर से और वाइन के लिए ₹25 प्रति बल्क लीटर और बीयर के लिए ₹100 प्रति बल्क लीटर की दर से अन्तरण फीस भी लगाई जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारण शुल्क, यदि कोई हो, की अंतर राशि का भुगतान भी करना होगा।
- (न) अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी पूरे राज्य में अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करने का हकदार होगा। अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी आगे अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करेगा। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों को पूरे राज्य में बार अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करने की भी अनुमति होगी।
- (प) अनुज्ञप्तिधारी, स्वीकृत परिसर में आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित करेगा और हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (2022 का 14), यदि लागू हो, के मानदंडों की अनुपालना करेगा।
- (फ) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) के थोक आउटलेट्स अर्थात् अनु-1खच अनुज्ञप्तिधारियों के पास जिला कार्यालय स्तर पर लाइव फीड की ऑनलाइन पहुंच के साथ प्रवेश, निकास और परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे होंगे।
- (ब) इस नियम के उपबंधों की अनुपालना होने पर विधि के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”;
- (xiv) खण्ड (i-छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(i-छ) प्ररूप अनु0-1-ग में अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस
- | | |
|---|---|
| (i) विस्की/स्कोच | ₹ 5,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (ii) बीयर | ₹ 3,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (iii) रम | ₹ 2,25,000 प्रति ब्राण्ड |
| (iv) जिन/वोदका | ₹ 1,25,000 प्रति ब्राण्ड |
| (v) वाइन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन | ₹ 25,000 प्रति ब्राण्ड |
| (vi) सीएसडी की आपूर्ति के लिए | ₹ 30,000 प्रति ब्राण्ड |
| वोदका/ब्राण्डी/ साईडर/वाइन तथा चैम्पेजन | |
| (vii) देसी मदिरा | ₹ 5,00,000 प्रति ब्राण्ड |
| (viii) पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी) | ₹ 1,50,000 प्रति ब्राण्ड |
| (ix) राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस | |
| (क) विस्की/स्कोच/रम/जिन/वोदका/ देशी मदिरा/बियर के प्रत्येक विशेष ब्रांड लेबल के लिए | ₹ 3,00,000/-प्रथम राज्य के लिए
₹1,00,000/-प्रत्येक बाद वाले राज्य के लिए |
| (ख) वाइन/ब्रांडी/साईडर/ चैम्पेजन/ पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी) | ₹1,50,000/-प्रथम राज्य के लिए
₹75,000/- प्रत्येक बाद वाले राज्य के लिए |
| (x) देश से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस | |
| (क) मदिरा के ब्रांडो के लिए ‘हरियाणा में निर्मित’ | ₹11,000/- |
| (ख) शेष ब्रांडो | ₹1,00,000/- |
| (xi) वर्ष के दौरान किसी भी अनुमोदित लेबल में बाद में कोई भी परिवर्तन | इस तालिका में क्रम संख्या (i)से (x) में वर्णित लागू फीस का 1/3”। |

3. उक्त नियमों में, नियम 27-क में उप-नियम (1) में,-

- (i) खण्ड (iii), (iv) तथा (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- “(iii) शापिंग माल में स्थित खुदरा अनुज्ञप्तिधारी ₹11,00,000: द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु0-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस

परन्तु अनु0-10ख अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य के किसी भी अनु0-1 खच अनुज्ञप्तिधारी या जिले के किसी भी अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी।

अनु0-10ख अनुज्ञप्तिधारी किसी भी अतिरिक्त मूल्यांकन फीस के भुगतान के बिना अपने जोन के आयातित विदेशी मदिरा के मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटा उठाने का हकदार होगा। ऐसा अतिरिक्त कोटा पहले से निर्धारित कोटा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा;

“(iv) प्ररूप अनु0-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी,—

जिला	अनुज्ञप्ति फीस
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत	₹4,00,000
नगर निगम, परिषद, समिति वाले अन्य जिलें	₹1,50,000

परन्तु अनु0-10ग अनुज्ञप्ति माईक्रोबुअरी द्वारा निर्मित बीयर की खुदरा बिक्री के लिए दी जाएगी। यह अनुज्ञप्ति अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारकों को दी जाएगी।

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति फीस के अलावा अनु0-10ग अनुज्ञप्तिधारियों से ₹2,00,000 की प्रतिभूति राशि ली जाएगी;

(v) प्ररूप अनु0-10ड में अनुज्ञप्ति के लिए फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी,—

जिला	अनुज्ञप्ति फीस
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला तथा सोनीपत	₹4,00,000
नगर निगम, परिषद, समिति वाले अन्य जिलें	₹1,50,000:

परन्तु अल्कोहल की कम मात्रा वाले पेय पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, नगर निगम/नगर परिषद/नगर समिति वाले शहरों में प्ररूप अनु0-10ड में एक अनुज्ञप्त खोला जाएगा। औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर में भी अनु0-10ड अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जाएंगी। राज्य में पर्यटन/साहसिक खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए, किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां आदि को अनु0-10ड के रूप में बार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का मामला, जिसमें आधारभूत संरचना और सुविधाएं हैं, लेकिन आबकारी नीति के सम्बन्धित खंडों में वर्णित भौगोलिक प्रतिबन्ध से बाहर स्थित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे सभी मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अपनी सिफारिश सहित सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

राज्य में अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारी बार सुबह 02.00 बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों के समय को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर सुबह 8:00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन अपनी पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। किसी भी आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) निकटतम दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बार लाईसेंसधारियों को राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेगा। बार लाईसेंसधारियों के लिए मूल्यांकन फीस और परमिट फीस की दरें निम्नानुसार होंगी:—

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹55 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाइन	₹45 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹35 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

पब अनुज्ञप्तिधारी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति के समान अतिरिक्त स्थानों, खुली जगह, छत, बालकनी आदि जैसी सुविधाओं के लिए हकदार होगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति फीस के अलावा अनु0-10ड अनुज्ञप्तिधारियों से ₹3,00,000 की प्रतिभूति राशि ली जाएगी।”।

(ii) खण्ड (v) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(vi) प्ररुप अनु0-10च में अनुज्ञप्ति के लिए फीस ₹10,00,000:

बशर्ते कि अनु0-10च अनुज्ञप्ति उन कॉर्पोरेट कार्यालयों को दिए जाएंगे जिनके पास एक ही परिसर में कम से कम एक लाख वर्ग फुट का कवर क्षेत्र है, जो स्व-स्वामित्व/पट्टे पर होगा और जिसके पास कम से कम 5000 कर्मचारी हों। अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों द्वारा परिसर में कम अल्कोहल की मात्रा वाले पेय (अर्थात् आरटीबी, बीयर, वाइन) रखने और उपभोग करने की अनुमति होगी। कैटीन/श्रेणी का न्यूनतम क्षेत्र, जहां ऐसे कॉर्पोरेट कार्यालय में अनु0-10च में अनुज्ञप्ति दिया जाएगा, दो हजार वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए।

अनु0-10च अनुज्ञप्तिधारियों को मूल्यांकन शुल्क और परमिट शुल्क के भुगतान के अधीन पसंद के अनुसार निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी शराब (बी0आई0ओ0) की खरीद की अनुमति दी जाएगी। किसी भी बी0आई0ओ0 ब्रांड की अनुपलब्धता के मामले में, उप आबकारी और कराधान आयुक्त (आबकारी) बार अनुज्ञप्तिधारियों को निकटतम से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद राज्य में किसी भी एल-1बीएफ अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे जैव ब्रांड खरीदने की अनुमति/सुनिश्चित करेंगे। दो अनु0-10च अनुज्ञप्तिधारी। बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारण शुल्क एवं परमिट शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी:-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹55 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाइन	₹45 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹35 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

इसके अलावा, अनुज्ञप्तिशुदा परिसर आम रास्ता नहीं होना चाहिए या जनता द्वारा अक्सर आने-जाने वाले किसी क्षेत्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त अनु0-10च अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ₹3 लाख की प्रतिभूति का भुगतान किया जाएगा। अनु0-10च के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।”

4. उक्त नियमों में, नियम 36-क में,-

(i) उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठेकों का आबंटन, तीन प्रकार के जोनों में बांटा जाएगा, जैसे शहरी जोन, ग्रामीण जोन और मिश्रित जोन। ग्रामीण जोन का कमाण्ड क्षेत्र, आबकारी व्यवस्था के अनुसार जोन में ग्रामीण ठेको/उप ठेको को स्थापित करने के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था के भाग के रूप में ऐसे कमाण्ड क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) सक्षम प्राधिकारी होगा। इसी तरह, मिश्रित जोन के मामले में, केवल ग्रामीण ठेको/उप ठेको को स्थापित करने के लिए कमाण्ड क्षेत्र आबकारी व्यवस्था में निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था में शहरी क्षेत्रों में ठेकों का स्थान निर्धारित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुज्ञप्तिधारी को आबकारी नीति/नियमों के अन्य प्रावधानों तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन के अधीन जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी दुकान (ठेके) लगाने की स्वतंत्रता होगी। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, आबकारी आयुक्त (वित्तायुक्त) एक स्पष्ट आदेश पारित करने के बाद किसी भी शहरी ठेके के स्थान को बदल सकता है। इसी प्रकार, किसी ग्रामीण ठेके या उप ठेके के मामले में भी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त), असाधारण परिस्थितियों में, जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर ऐसे ठेके/उप ठेके के स्थान को स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है।

अनुज्ञप्तिधारी, जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा स्थल योजना के पूर्वानुमोदन से ठेका (ठेके) और उप-ठेका (उप-ठेके) खोलने की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा। जिले में स्थित सभी अनु0-2/अनु0-14क ठेकों, उप ठेकों और शराबखाने की लोकेशन संबंधित उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा मैपड/जियो-टैगड की जाएगी और विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

खुदरा अनुज्ञप्तियां (अनु0-2 और अनु0-14क) एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए जाएंगे, यानी 12.06.2023 से 11.06.2024 तक जिसे इसके बाद नीति वर्ष या नीति वर्ष 2023-24 के रूप में संदर्भित किया जाएगा। नीति अवधि को निम्नानुसार चार तिमाहियों में विभाजित किया जाएगा:-

तिमाही	अवधि
प्रथम	12 जून, 2023 से 11 सितम्बर, 2023
द्वितीय	12 सितम्बर, 2023 से 11 दिसम्बर, 2023
तृतीय	12 दिसम्बर, 2023 से 11 मार्च, 2024
चतुर्थ	12 मार्च, 2024 से 11 जून, 2024

प्रत्येक तिमाही को आगे 3 महीनों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक आबकारी माह कैलेंडर माह के 12वें दिन से शुरू होगा और बाद के कैलेंडर माह के 11वें दिन समाप्त होगा।

परन्तु किसी भी कारण से किसी भी मामले में, मुख्य ग्रामीण ठेके को बन्द करना पड़ता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को उस जोन के कमाण्ड क्षेत्र में उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्व स्वीकृति के साथ स्थानांतरित करेगा।

जोन की ईकाईयों में देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दुकानों का आबंटन किया जायेगा। एक जोन में अधिकतम दो ठेके शामिल होंगे, जो आबकारी व्यवस्था में प्रदर्शित किए जाएंगे। जोनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

- शहरी क्षेत्रों में 02 खुदरा ठेके हैं, दोनों शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें पहले से स्थान है;
- ग्रामीण क्षेत्रों में 02 खुदरा ठेके हैं, दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, अनुज्ञप्तिधारी को अपने कमाण्ड एरिया में कहीं भी इन दुकानों का स्थान तय करने के लिए लचीलेपन के साथ,
- 02 खुदरा ठेकों तक के मिश्रित क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में पहले से निर्धारित स्थान के साथ इतनी संख्या में ठेका (ठेकों) के साथ, जैसा कि आबकारी व्यवस्था में नियत किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में शेष ठेका (ठेके) (अनुज्ञप्तिधारी को उसके कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी स्थान नियत करने के लिए लचीलेपन के साथ) इस तरह के जोन शहरी ठेका (ठेके) के स्थान के निकटता में। ठेकों की स्थापना नीति के अन्य प्रावधानों की अनुपालना के अधीन होगी।

आबंटन की प्रक्रिया, सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त से मिलकर बनने वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई-निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो, संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा।

आबकारी व्यवस्था तैयार होने के उपरान्त, इसे जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय, जिला के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) के कार्यालय में तथा विभागीय वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा आबकारी व्यवस्था के प्रदर्शित करने के पश्चात् दो दिन के लिए सार्वजनिक/हितधारकों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और दो दिन के लिए भीतर यदि कोई आक्षेप है तो उसका निर्णय किया जाएगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और ठेकों के अन-अलॉटिड जोन का आबंटन, निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति में आरक्षित मूल्य कम करके जारी रखा जाएगा:-

- यदि जोन की आरक्षित मूल्य 5.00 करोड़ रुपये से कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत के स्लैब में;
- यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के अधिकतम 3 प्रतिशत तक के स्लैब में, जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 4 जुलाई, 2023 तक, या अगले कार्यदिवस को, यदि 4 जुलाई, 2023 को छुट्टी होती है, जो भी पहले हो। ऐसे मामले में जोन का कोटा कम किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) कोटा निर्धारित करने में अन्तिम प्राधिकारी होगा। तथापि जोन जोन के आबंटन से पूर्व कोटा में न्यूनतम कमी व्यतीत दिनों की संख्या के अनुरूप होगी।;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का अधिकतम दस प्रतिशत तक कम किया जाएगा, जैसा कि आबकारी एवं कराधान

आयुक्त इस उद्देश्य के लिए उचित समझें और आमन्त्रित ई-निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आबंटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा की गई किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मूल अनुज्ञप्तिधारी/अलॉटी उत्तरदायी होगा। तथापि, यदि मूल बोली से अधिक बोली प्राप्त होती है तो मूल अलॉटी को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

(2) देशी शराब (अनु0-14क) तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु0-2) के खुदरा जोनों का आबंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी रीति में ई-निविदाएं आमंत्रित करके किया जायेगा। ई-निविदा आमंत्रण के संबंध में की विस्तृत प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिसे विभाग की वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर अपलोड कर प्रदर्शित किया जाएगा। बोली में भाग लेने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, आवेदक (आवेदकों) की आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञप्तियों के सभी आबंटन आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) के अनुमोदन के अधीन हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) बिना कोई कारण बताए किसी भी आबंटन को जनहित में आबंटन की तिथि से 10 दिन के भीतर अस्वीकार कर सकते हैं। यदि आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) का कोई निर्णय दस दिन की निर्धारित अवधि के भीतर सूचित नहीं किया जाता है, तो आबंटन को आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।

सभी अनुज्ञप्तियाँ, चाहे थोक के लिए या खुदरा बिक्री के लिए, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों और समय-समय पर हरियाणा राज्य के लिए लागू नियमों/विनियमों/निर्देशों/नीतियों के अधीन प्रदान की जाएंगी।”;

(ii) उप-नियम (4) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेगे, अर्थात्:-

“(4) प्रत्येक बोलीदाता को उसकी बोली के साथ अग्रिम धन देनी होगी। अग्रिम धन केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में भुगतानयोग्य होगी। बैंक ड्राफ्ट आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला के पक्ष में भुगतानयोग्य होगा।

अग्रिम धनराशि निम्न अनुसार होगी:-

क्रम संख्या	जोन का आरक्षित मूल्य	अग्रिम धनराशि
(i)	₹3 करोड़ से कम	₹12.5 लाख
(ii)	₹3 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹5 करोड़ से कम	₹25 लाख
(iii)	₹5 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹10 करोड़ से कम	₹50 लाख
(iv)	₹10 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹25 करोड़ से कम	₹75 लाख
(v)	₹25 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹40 करोड़ से कम	₹100 लाख
(vi)	₹40 करोड़ तथा अधिक	₹150 लाख।

(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹1,50,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी-योग्य तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उसकी रजिस्ट्रेशन के जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी। नकद के मामले में, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय द्वारा एक विधिवत हस्ताक्षरित रसीद जारी की जाएगी।”;

(iii) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0-14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला में स्थित देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा :-

तिमाही	मास	कोटा प्रतिशत में		
		मास वार कोटा	तिमाही वार कोटा	तिमाही वार संचित कोटा
प्रथम	12 जून, 2023 से 11 जुलाई, 2023	9 प्रतिशत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत
	12 जुलाई, 2023 से 11 अगस्त, 2023	8 प्रतिशत		
	12 अगस्त, 2023 से 11 सितम्बर, 2023	9 प्रतिशत		

द्वितीय	12 सितम्बर, 2023 से 11 अक्टूबर, 2023 12 अक्टूबर, 2023 से 11 नवम्बर, 2023 12 नवम्बर, 2023 से 11 दिसम्बर, 2023	7 प्रतिशत 9 प्रतिशत 10 प्रतिशत	26 प्रतिशत	52 प्रतिशत
तृतीय	12 दिसम्बर, 2023 से 11 जनवरी, 2024 12 जनवरी, 2024 से 11 फरवरी, 2024 12 फरवरी, 2024 से 11 मार्च, 2024	10 प्रतिशत 9 प्रतिशत 8 प्रतिशत	27 प्रतिशत	79 प्रतिशत
चतुर्थ	12 मार्च, 2024 से 11 अप्रैल, 2024 12 अप्रैल, 2024 से 11 मई, 2024 12 मई, 2023 से 02 जून, 2023	7 प्रतिशत 7 प्रतिशत 7 प्रतिशत	21 प्रतिशत	100 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार उसे आबंटित कोटा का 100 प्रतिशत कोटा उठाना होगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा उठाने में असफल होने पर अल्प कोटा शास्ति लगेगी। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी को पिछली तिमाही का न उठाया गया कोटा अगली तिमाही में उठाना होगा।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अनुपालन में देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 150/- रुपये तथा 200/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।”;

(iv) उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(19) कोई भी व्यक्ति, जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा, जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डे तथा पूजा के स्थल के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। बशर्ते कि शहरी खुदरा शराब की दुकानों के मामले में, आबकारी आयुक्त संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्केट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थल वर्ष 2023-24 में ठेके की स्थापना के पश्चात् वर्ष के चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।”;

(v) उप-नियम (21) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(21) प्राकृतिक आपदा जैसे कि अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि के कारण या दंगों के कारण या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा निवारक बंदी के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति या राहत अनुज्ञेय नहीं होगी।”;

(vi) उप-नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(22) आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम, राज्य में महानगरीय विकास प्राधिकरणों (जैसे जीएमडीए, एफएमडीए, पीएमडीए आदि), हरियाणा पर्यटन निगम, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों इत्यादी की भूमि में उच्च राजस्व क्षमता वाले शराब के ठेकों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा, जहां भी संभव हो। तथापि, उसका किराया अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सीधे ऐसे विभाग/निगम को भुगतान किया जाएगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) किराए का भुगतान सुनिश्चित करेंगे और आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मासिक आधार पर रिपोर्ट भेजेंगे।”;

(vii) उप-नियम (24) से 27 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को अवंत ग्रेड आउटलेट में परिवर्तित करेगा, जहाँ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबंटित अवंत ग्रेड आउटलेट के रूप में पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट को क्षेत्र के ग्राहक-गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगा। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ऐसे ठेके के मूल कोटा, जोन के मूल कोटा को जोन में ठेकों की संख्या से विभाजित करके निकाला जायेगा।

अनुज्ञप्तिधारी स्वीकृत परिसर में आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित करेगा और हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022, यदि लागू हो, के मानदंडों का अनुपालन करेगा।

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रविजन सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बिल जारी करने की मांग पर आवश्यक होगा। भारत में बनी विदेशी शराब तथा देशी शराब के लिए अलग पॉस मशीनें सभी खुदरा विक्रेताओं के बिक्री काउंटर पर स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को विभाग द्वारा निर्धारित

पॉस के एकीकृत समाधान को अपनाने की आवश्यकता होगी। यह उपबन्ध बार अनुज्ञप्तिधारियों जैसे अनु0-4/अनु0-5, अनु0-12ग, अनु0-12गग तथा अनु0-10ड आदि पर भी लागू होगा।

इस प्रावधान के उल्लंघन की दशा में प्रथम 10 उल्लंघनों पर ₹5000 प्रति उल्लंघन, अगले 10 उल्लंघनों पर ₹10000 प्रति उल्लंघन तथा अगले 10 उल्लंघनों पर ₹5000 प्रति उल्लंघन की दर से जुर्माना संबंधित आबकारी अधिकारी द्वारा जाँच उपरांत अनुज्ञप्तिधारी पर लगाया जायेगा। किसी भी बाद के उल्लंघन के मामले में, संबंधित उप आबकारी और कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा जांच के बाद, प्रतिभूति की जब्ती के साथ अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा।

आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि शहरी क्षेत्रों में कोई खुदरा अनुज्ञप्तिधारी अपने जोन की फीस; (क) गुरुग्राम और फरीदाबाद के मामले में ₹15 करोड़ के बराबर या उससे अधिक; (ख) शेष जिलों के मामले में ₹5 करोड़ के बराबर या उससे अधिक रखने वाले, जो ठेकों के आबंटन के बाद अपने ठेके को अवंत ग्रेड आउटलेट में बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी समिति द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।

(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत नवीनीकरण आवेदन के प्रस्तुत करने के दिन या ई-बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 11 जून, 2023 को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 18 जून, 2023 तक जमा कराई जाएगी।

यदि बोली आरक्षित मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक है, तो बोलीदाता को जमा प्रतिभूति राशि स्लैब के अनुसार, जो राशि लागू है, के अलावा अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।

उसकी बोली की धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस का तिरासी (83) प्रतिशत मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो मास जून, 2023 से शुरू होने वाले प्रत्येक कैलेंडर मास के अन्तिम दिवस तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतानयोग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 83 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसके बोली धन/अनुज्ञप्ति फीस के 17 प्रतिशत के बराबर उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित की जाएगी। समायोजन उसकी बोली की धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 8.5 प्रतिशत की प्रत्येक दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा;

(26) उसके बोली धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति जुलाई, 2024 के अन्त तक उसकी ओर बकाया या असंदत पाई गई किसी राशि का समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। किस्तों की अनुसूची निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

मास	किस्तें (प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के संदर्भ में)
जून	8.5
जुलाई	8.5
अगस्त	8.5
सितम्बर	8.5
अक्टूबर	8.5
नवम्बर	8.5
दिसम्बर	9.1
जनवरी	9.1
फरवरी	9.1
मार्च	4.7

यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। दस किस्तों में से किसी भी किस्त के भुगतान के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं करने की स्थिति में विलम्ब भुगतान पर ब्याज देय होगा। यदि किसी माह की किस्त (या उसके भाग) का भुगतान अगले कैलेंडर माह के 11वें दिन तक

किया जाता है, तो विलंबित भुगतान की राशि पर चूक के दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। हालांकि, यदि चूक अगले कैलेंडर माह के 11 वें दिन से आगे जारी रहता है, तो चूक के पॉलिसी महीने के पहले दिन से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

यदि किसी भी क्षेत्र का कोई ठेका/ठेके बन्द किया जाता है या बाद में कोविड कंटेनमेंट जोन में आने की वजह से बन्द कर दिया जाता है, तो इसकी अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को बन्द होने के दिन के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। बन्द किए गए ठेके की अनुपातिक अनुज्ञप्ति फीस और कोटा की गणना करने के उद्देश्य हेतु, जो माफ की जानी है, जोन की अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को जोन के सभी मुख्य ठेकों के बीच बराबर रूप से विभाजित किया जाएगा।

(27) जोन के ठेकों की दशा में, जो चालू आबकारी वर्ष के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन की तिथि से दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है, के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में 31 मार्च, 2023 तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी;

यदि आबंटन या पुनः आबंटन फरवरी, 2024 के बाद किया जाता है, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तीय आयुक्त) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान और कोटा उठाने की समय सारणी इस तरह से तय करेंगे जैसा वह उचित समझे।

आबंटन/पुनः आबंटन मास के भुगतान की तिथि मास के अन्तिम दिवस को होगी।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 37 में—

(i) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(2) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विहित परिसर के सिवाय (जिन्हें इसमें, इसके बाद उक्त अनुज्ञप्ति परिसर कहा गया है) पर कोई ऐसा कारोबार या अनुज्ञप्ति के अधीन मान्य शराब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की शराब नहीं रखेगा। कलैक्टर केवल विशेष मामलों में, जहाँ अनुज्ञप्त स्थान पर अधिक मात्रा में शराब रखने की जगह न हो, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्त स्थान के अतिरिक्त खुदरा बिक्री से अधिक मात्रा में शराब किसी अन्य स्थान पर रखने हेतु 5,00,000/—रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस की अदायगी पर अनुमति प्रदान करेगा। कलैक्टर ऐसी अनुमति देने से पूर्व स्वयं की सन्तुष्टि करेगा कि प्रस्तावित स्थान पूर्ण रूप से सुरक्षित है और यह आम जनता की पहुँच से दूर है। अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक अग्निशमन उपकरण भी स्थापित करेगा और यदि लागू हो तो हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के मानदंडों का पालन करेगा।

इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी अनु0-1/अनु0-13/अनु0-1ख/अनु0-1-ख1/अनु0-1कख/ अनु0-1कख1/अनु0-1ख1क/अनु0-1खच के सभी थोक अनुज्ञपितशुदा परिसरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगा और इन सीसीटीवी कैमरों से लाइव फीड संबंधित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवेश, निकास और बिलिंग काउंटर सहित संबंधित क्षेत्रों को कवर करने वाले सभी खुदरा शहरी दुकानों और शराबखाना में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।”;

(ii) उप नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(8) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय लाउडस्पीकर, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से शराब की बिक्री की घोषणा करके उसका विज्ञापन नहीं दे सकता है। शराब की उपलब्धता के सभी संकेत और विज्ञापन प्रतिबन्धित रहेंगे। खुदरा अनुज्ञप्तिधारी दुकान के अन्दर और आस-पास सफाई और स्वच्छता बनाए रखेंगे। ठेके और शराबखाने के अन्दर और बाहर पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान रखे जाने चाहिए। रात के समय रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाए। अनुज्ञप्तिधारी का नाम और वर्ष जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, खुदरा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेको के साथ-साथ उप- ठेको पर उचित आकार के एक बोर्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाएगा बशर्ते कि वह अन्य सभी वैधानिक मानदंडों और निर्देशों को पूरा करता हो। इसके अलावा, एक साइनबोर्ड भी लगाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:

शराब पीकर गाड़ी न चलाएँ

अनुज्ञप्ति का नाम	
अनुज्ञप्ति का सम्पर्क सूत्र	
अनुज्ञप्त नम्बर	

ठेके का प्रकार (ठेका/उप-ठेका)	
उप-ठेके का क्रम संख्या, यदि लागू है	
वर्ष के लिए वैध	
आबकारी निरीक्षक का सम्पर्क सूत्र	
उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय का सम्पर्क सूत्र	
ठेका का खुलने तथा बन्द होने का समय	

आगे, अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न ब्राण्डों के बिक्री मूल्य भी प्रदर्शित करेगा।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप-नियम (16क) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(छ) (क) उप-ठेका खोलने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप अनु0-14क, अनु0-2/एस0वी0 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उप-ठेका उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्व अनुमति के अधधीन जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर खोलने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक उप-ठेके की फीस निम्नलिखित होगी:-

ग्राम की जनसंख्या	प्रति उप-ठेके की अनुज्ञप्ति फीस (रूपये में)
1000 तक	1.50 लाख
1001-10000	3.00 लाख
10001 तथा उपर	4.50 लाख

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-ठेकों के लिए प्रावधान, नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) और (घ) के अनुसार लागू होंगे,-

- (ख) एक गांव में एक उप-ठेके की अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसे गांव की आबादी 4000 तक है;
- (ग) एक गाँव में दो उप-ठेकों की अनुमति होगी, यदि ऐसे गाँव की जनसंख्या 4000 से अधिक तथा 8000 से कम;
- (घ) एक गाँव में तीन उप-ठेकों की अनुमति होगी, यदि ऐसे गाँव की जनसंख्या 8000 से अधिक है।

टिप्पण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए, “गाँव की जनसंख्या” का अर्थ दिनांक 15.05.2023 को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित परिवार सूचना डेटा रिपोर्टिगरी (एफ0आई0डी0आर0) के अनुसार गाँव की जनसंख्या है।

आगे यह स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष गाँव में उप-ठेकों की संख्या उस विशेष गाँव में मुख्य ठेका/ठेकों की संख्या के बावजूद है।”।

अशोक कुमार मीना,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th June, 2023

No. 19/X-I/P.A.1/1914/S.59/2023.— In exercise of the powers conferred under section 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.55/X-1/P.A.1/1914/S.9/2022, dated the 6th September, 2022, I, Ashok Kumar Meena, Excise Commissioner, Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

- (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2023.
- In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24,-
 - for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) for a license in form L-1,-

- (a) ₹1.65 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is less than or equal to 10 lakh Proof Litre.
- (b) ₹2.00 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 10 lakh Proof Litre and less than or equal to 25 lakh Proof Litre.
- (c) ₹2.25 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 25 lakh Proof Litre and less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.
- (d) ₹3.00 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is above 50 Lakh Proof Litre:

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security/bank guarantee equivalent to 30 % of the license fee for each L-1 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act:

Provided further that in case L-1 licensee is found to be indulging in any illegal or clandestine sale of liquor in order to avoid additional excise duty, the amount becoming due on account of penalty etc. towards such L-1 licensee shall also be recoverable from the security deposited by him of his retail outlets (L-2) licenses and in case of shortage in the stock of any L-1 godown is found more than 15,000 Proof Litre and upto 30,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 1.5 times the additional excise duty payable on such stock. In case of shortage in the stock of any L-1 godown is found more than 30,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 2 times the additional excise duty payable on such stock and a breakage of allowance of 0.5% on Indian Made Foreign Liquor, all other remaining type of liquor and 1% on beer shall be allowed. The Excise duty levied in respect to the breakage stock shall not be refunded/adjusted.”;

(ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

- (a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels ₹ 25,00,000
of 5 Star grading and above:

Provided that L-4/L-5 licenses may also be granted to hotels and restaurants within the area notified under Gurugram-Manesar Urban Complex Plan 2031 and also such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Information Technology Park Manesar, Information Technology Park, Panchkula etc. L-4/L-5 licenses may also be granted to the reputed restaurants in the industrial towns Dharuhera and Bahadurgarh and reputed hotels and restaurants situated in the Morni sub-Tehsil area:

Provided further that such licensee shall be allowed one main bar and three additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. In case the licensee wishes to sub-lease one or more additional points, then a fixed fee of Rs.10 Lakh per additional point shall be charged from such licensee. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

- (b) Hotels having grading of 4 Star: ₹ 20,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted provisionally to a Hotel located anywhere in the State subject to the condition that the applicant shall procure star classification of 3 star and above from the Ministry of Tourism, Government of India within one year of grant of such license, failing which the provisional license shall not be renewed

subsequently. The licensee shall apply for the star rating within one month of obtaining the L-4/L-5 license:

- (c) for Hotels having grading of 3 Star,-

Serial number	Name of District	License fee
1.	Gurugram	₹ 18,00,000
2.	Faridabad, Panchkula and Sonapat	₹ 14,00,000
3.	All other Districts	₹ 10,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted to three star and above categories of star hotels located anywhere in the State. In order to promote tourism/adventure sports tourism in the State, the case for grant of a bar license in form L-4/L-5 to any reputed hotel, resort and restaurant etc., having good infrastructure and facilities, but located beyond geographical restriction as mentioned in relevant clauses of the Excise policy, may be considered by the Government. All such cases shall be sent by the Excise and Taxation Commissioner with his recommendation to Government for approval.

The license of existing functional bars located anywhere in the State shall be renewed by the concerned Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), on behalf of the Collector.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in up to three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one-time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 licensees shall procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹55 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹45 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹35 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-4/L-5 licensees in addition to the license fee.”;

- (d) For a license in form L-4/5, for clause (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:-

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| (a) | for district Gurugram | ₹16,00,000/- |
| (b) | for district Faridabad, Panchkula and Sonapat | ₹12,00,000/- |
| (c) | for all other districts in the State except Gurugram, Faridabad, Panchkula and Sonapat | ₹8,00,000/- |
| (d) | for Bar(s) operated by Haryana of Tourism Corporation in all districts | A composite fee
₹ 1,50,00,000/- |
| (e) | Bars operated by Haryana Shahri of Vikash Pradhikaran in their Gymkhana and Golf Clubs in all districts: | A composite fee
₹ 1,50,00,000/- |

Provided that a composite security of ₹6,00,000 Lacs shall be taken from Haryana Tourism Corporation and Haryana Sahari Vikash Pradhikaran in addition to the composite license fee.

Provided further that if any L-4/L-5 licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur or sale of unaccounted liquor or sale of liquor without holograms/EALs, his license shall be cancelled forthwith and or the security amount

shall be forfeited. Such licensee and premises may also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s).

Note 1. - Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license may be allowed.

Note 2.- In case of bars operated by Haryana Tourism Corporation and Haryana Shahri Vikash Pradhikaran in their Gymkhana and Golf Clubs, they shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹ 1 lakh for each such point.”;

(iii) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely :-

“(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit and Beer shall be levied as under: -

		For supply within State	For supply outside State within India	Export out of India
(a)	For D-2 licenses bottling their own brands	₹14.00/-per Proof Litre	₹4.50/-per Proof Litre	Nil
(b)	For bottling plants bottling their own brands	₹18.00/-per Proof Litre	₹7.00/-per Proof Litre	Nil
(c)	For bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied	₹22.00/- per Proof Litre	₹7.50/- per Proof Litre	Nil
(d)	For bottling of beer by the brewers	₹11.00/- per Bulk Litre	₹1.00/- per Bulk Litre	Nil

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.”;

(iv) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that a temporary license in form L-12A shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned to an individual for serving liquor during a day beyond possession limit. An online application for the grant of license L-12A shall be made for the following places for hosting any personal function, get-together or marriage function etc:-

- for serving liquor in banquet Halls, Hotels, Clubs, Restaurant, Farm Houses, Community Centres, Public Parks/Places of Haryana Sahari Vikash Pradhikarn and dharamshalas.
- for licensed Hotels, Restaurant and Clubs for serving liquor outside their licensed premises on a temporary basis on a specific day.
- Any other private place.

The commercial places like Banquet Halls, Hotels having Party Hall/Lawns shall have to mandatorily register with the Excise Department in the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the respective district. The annual registration/renewal fee of Banquet Halls and Hotels having Party Halls/Lawns shall be as under:-

Serial No.	Location of Banquet Hall/Hotel	Annual Registration fee
1	Within the limits of Metropolitan Development Authorities like GMDA, FMDA and PMDA etc.	₹1,00,000
2	Within the Municipal Corporation limits of Ambala, Hisar, Karnal, Panipat, Rohtak, Sonapat & Yamunanagar.	₹50,000
3	Other Municipal Council/Committee limits	₹25,000

4	Banquet Halls/Hotels falling on National/State Highway outside the Municipal limit of a District (subject to the provision of Excise Policy and Excise rules).	₹25,000
5	Banquet Halls falling in Rural Areas (other than those specified in above categories)	₹10,000

The fee structure for L-12A license shall be as under:-

(i)	For person serving liquor at commercial venues	₹5,000/- per day per function
(ii)	For individual serving liquor at a private place beyond the possession limit	₹1,000/- per day per function :

The temporary license in form L-12A license shall not be granted in the licensed premises of any Club, Hotel or Restaurant. The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall also contain the details like name and GSTIN of caterer, the approximate number of guests and the quantity of liquor to be served:

Provided further that in case liquor is served at any Banquet Hall or Hotel etc. without a valid L-12A License, a penalty of ₹50,000/- shall be imposed for first offence, ₹1,00,000/- for second and ₹1,50,000/- for third offence against the Owner/Management/ Authorized Person of such Banquet Hall or Hotel. Further, in case of subsequent violations, such Banquet Hall or Hotel shall be debarred for grant of any excise license/permit for a period of one year.”.

for temporary license in form L-12AA.-L-12AA license shall be granted to any person including event organizers for serving liquor during the events like entertainment shows, exhibitions, comedy shows, magic shows, mega shows, celebrity events and other similar events on payment of application fee, as mentioned below:-

No. of persons attending such event	Application fee per event per day (in ₹)
Upto 5000	₹50,000/-
5001 to 25000	₹2,50,000/-
25001 or above	₹10,00,000/-

This licence may be applied for a maximum period of three days at a time and shall be granted by Excise and Taxation Commissioner. In addition to application fee, the applicant shall also be required to deposit in advance Excise Duty, Assessment Fee, VAT and other Government levies as applicable on such liquor.

The L-12AA licensee shall pay Assessment Fee on Foreign Liquor and Beer at following rates:-

Liquor Type	Rate of Assessment Fee
IMFL/IFL (BIO)	₹450 per Proof Litre
Beer/RTB/Wine and any other category	₹300 per Bulk Litre

The VAT shall be payable by L-12AA licensees at the rates as applicable to bar licensees.

(v) for clause (iv-b), the following clauses shall be substituted, namely :-

“(iv-b) for a license in form L-12C,-

Category	Type of license	District	Annual License fee	Additional points (Count/License fee)
(i)	L-12 C granted to a club of repute	For the districts having Metropolitan Development Authority	₹ 20,00,000/-	As per provisions applicable to L-4/ L-5 license with 3 Star rating

		For other districts	₹ 10,00,000/-	
(ii)	L-12 C granted in a residential condominium	Gurugram	₹ 15,00,000/-	As per provisions applicable to L-4/L-5 license having no star rating.
		Faridabad	₹ 12,00,000/-	
		All other districts	₹ 8,00,000/-	

Provided that L-12C licenses may be granted to the Clubs of repute situated anywhere in the State. L-12C licenses may also be granted in a residential condominium situated anywhere in the State.

This will be subject to the condition that only the residents of the condominium or their guests shall be allowed to utilize the facilities in a club having L-12C License:

Provided further that in case of L-12C license granted to any army sponsored club like Sirhind Club, Ambala, the army officials shall be allowed to utilize their quota through CSD canteen while the civilian members shall not be entitled for the liquor supplied through CSD canteen. The license fee for such club shall be ₹5 lakh per annum.:

Provided further that if any L-12C licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur or sale of unaccounted liquor or sale of liquor without holograms/EALs, his license shall be cancelled forthwith and or the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s).

The L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-:

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹55 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹45 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹35 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

L-12C licensee bars may remain open up to 02.00 A.M. in the State. The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of Rs.20 Lakh per annum. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-12C shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT:

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12C licensees in addition to the license fee.”;

Note:- Any additional point, except the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.”;

- (vi) for clause (iv-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(iv-c) for a license in form L-12CC,-

- (a) Golf Club with the capacity ₹ 30,00,000/-
Up to 9 holes (with 2 sale points).
- (b) Golf Club with the capacity ₹ 50,00,000/-
Up to 18 holes (with 3 sale points).

Provided that license to serve liquor may only be granted to Golf Clubs having facilities of 9 holes or more and they shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or any type of bar license. The L-12CC Club bar licensee can remain open up to 02.00 A.M. in the State. The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of ₹20 Lakh per annum. The L-12CC Club bar licensee shall be allowed to open two more additional points on

payment of a fee equal to ₹10 Lakh per additional point. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-12CC shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

The L-12CC licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹55 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹45 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹35 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

Provided further that if any L-12CC licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pgs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur or sale of unaccounted liquor or sale of liquor without holograms/EALs, his license shall be cancelled forthwith and or the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s):

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12CC Club bar licensees in addition to the license fee.”;

(vii) in clause (v), for sub-clause (i) and entries thereagainst, the following sub-clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(i) The annual license fee for the wholesale outlet of country liquor (L-13) shall be as under:-

- (1) ₹60.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or less than 25 lakh Proof Litre.
- (2) ₹75.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is more than 25 Lakh and less than 50 Lakh Proof Litre.
- (3) ₹100.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or more than 50 Lakh Proof Litre.

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security/bank guarantee equivalent to 50 % of the license fee for each L-13 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act:

Provided further that in case L-13 licensee is found to be indulging in any illegal or clandestine sale of liquor in order to avoid additional excise duty, the amount becoming due on account of penalty etc. towards such L-13 licensee shall be recoverable from the security deposited by him of his retail outlets (L-14A) licenses and in case shortage in the stock of any L-13 godown is found more than 10,000 Proof Litre and upto 20,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 1.5 times the additional excise duty payable on such stock. In case shortage in the stock of any L-13 godown is found more than 20,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 2 times the additional excise duty payable on such stock. A breakage of allowance of 0.5% on Country Liquor including Metro shall be allowed. The Excise duty levied in respect of the breakage stock shall not be refunded/adjusted.”;

(viii) for clause (i-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-c) for a license in form L-1AB,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1AB, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is equal to or less than 25 Lakh Proof Litre	₹40,00,000;”
2.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 25 Lakh Proof Litre & less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.	₹60,00,000;”

3.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 50 Lakh Proof Litre & less than or equal to 100 Lakh Proof Litre.	₹110,00,000;”
4.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 100 Lakh Proof Litre.	₹150,00,000;”
As soon as the sale of L-1AB Licensee in the policy year 2023-24 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

- (ix) for clause (i-cc) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-cc) for a license in form L-1AB1,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is equal to or less than 50 Lakh Bulk Litre.	₹ 50,00,000;”
2.	In case the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 50 Lakh Bulk Litre and less than or equal to 100 Lakh Bulk Litre .	₹100,00,000;”
3.	In case the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 100 Lakh Bulk Litre.	₹150,00,000;”
As soon as the sale of L-1AB1 Licensee in the policy year 2023-24 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

- (x) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-e) for a license in form L-1B,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1B, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is equal to or less than 25 Lakh Proof Litre	₹30,00,000;”
2.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 25 Lakh Proof Litre & less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.	₹70,00,000;”
3.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 50 Lakh Proof Litre & less than or equal to 100 Lakh Proof Litre.	₹125,00,000;”
4.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 100 Lakh Proof Litre & less than or equal to 250 Lakh Proof Litre.	₹175,00,000;”
5.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 250 Lakh Proof Litre.	₹400,00,000;”
As soon as the sale of L-1B Licensee in the policy year 2023-24 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.		

- (xi) In clause (i-ee),- for sub-clauses (a) and (b) and entries thereagainst, the following sub-clauses and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) for a license in form L-1B-1 (for beer),-

(I) In case of new License or where the annual sale of Beer by L-1B-1, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is equal to or less than 50 Lakh Bulk Litre	₹35,00,000;”
(II) In case the annual sale of Beer by L-1B-1, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 50 Lakh Bulk Litre.	₹125,00,000;”

Provided that as soon as the sale of Beer by L-1B-1 Licensee in the policy year 2023-24 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.

(b) for a license in form L-1B-1 (for wine) ₹25,00,000;”.

(xii) for clause (i-eee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-eee) for a license in form L1-B1-A (Ready to Drink Beverages),-

1.	In case of new License or where the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is equal to or less than 1 Lakh Bulk Litre	₹10,00,000;”
2.	In case of new license or where the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 1 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 4 Lakh Bulk Litre.	₹20,00,000;”
3.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 4 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 8 Lakh Bulk Litre.	₹50,00,000;”
4.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2022-23 (i.e. from 12-06-2022 to 11-06-2023), is more than 8 Lakh Bulk Litre.	₹100,00,000;”
As soon as the sale of L1-B1-A Licensee in the policy year 2023-24 exceeds higher threshold, as prescribed in the above categories, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;		

(xiii) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -

“(i-eeee) for a license in form L-1BF. –

- (a) The annual license fee for L-1BF shall be ₹4,00,00,000.
- (b) The license shall be granted by inviting online applications through departmental portal.
- (c) In case, the number of eligible applications received in first round is more than or equal to sixteen (16), the L-1BF licence shall be granted to all the eligible applicants. In such a case, the department shall not initiate any further round(s) for allotment of L-1BFs in the State.

Provided that in case, the number of eligible applications received in first round is less than sixteen (16), the department shall initiate more round(s) for allotment of remaining L-1BF licences. The number of remaining L-1BF licenses can be calculated by subtracting the count of L-1BF allotted in all previous round(s) from sixteen (16).

Provided further that in case, the number of eligible applications in second or any subsequent round exceeds the remaining number of L-1BF licensees available for allotment in that particular round, then the grant of such remaining L-1BF licence(s) shall be made by draw of lots amongst eligible applicants of that particular round.

- (d) The applicant shall be allowed to make only one application. The applicant shall be, a wholesale licensee in the State of Haryana or any other State, or a proprietor firm or a partnership firm, or, a company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a society registered under the relevant law or a firm registered under Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009).
- (e) The applicant shall deposit an application fee of ₹2,00,000. The application fee shall be non-refundable and non-adjustable. The application shall also be accompanied with an earnest money of ₹ 25,00,000. The application shall be accompanied with documents establishing the identity of the applicant. Identity proof(s) of all the person(s), like proprietor, all the partners, directors and the authorized person, if there is any one so authorized, should be uploaded online along with the application.
- (f) All the applications which are found in order in accordance with the provisions of excise law shall be considered as eligible. The Department shall publish list of eligible applicants on its official website and, this will be treated as date of allotment of his

license. The license shall be valid from the day of grant of license or 12th June, 2023 whichever is later.

- (g) The eligible applicant shall deposit a security amount equal to 25% of the license fee within a week of the date of allotment, or within such time, as may be prescribed in the notice. The earnest money shall be adjustable towards the payment of amount of security. The licensee shall also be required to declare the storage capacity of his liquor godown at the time of grant of license.
- (h) The earnest money of the applicant shall be forfeited in the following cases:-
 - (i) If he fails to deposit security amount within the prescribed time, or
 - (ii) If any successful applicant fails to furnish documents as he is required to submit in the office within seven days of the allotment, or
 - (iii) In case the applicant is found to have furnished any false information or forged documents in his application, or
 - (iv) If he is found guilty of indulging in any malpractice, or
 - (v) For any other reasons as the Excise Commissioner may think fit.
- (i) The eligible applicant shall have to submit all other documents as are specified in the public notice, instructions issued from time to time, provisions of the Haryana Excise Act, 1914 and the rules framed there under.
- (j) The applicant shall be treated as licensee once he has deposited his security amount.
- (k) The licensee shall pay the license fee in eight monthly installments each equal to 10% of the license fee. The first of the eight installments shall be paid by the last day of the calendar month of allotment. The remaining seven installments shall be paid by 15th of each month, starting from the month following the month of allotment, till all seven installments are received.

In case, the license is granted after the month of September, 2023, the 80% of the license fee shall be divided equally into monthly installments in such a manner that the whole amount is received by the 15th April, 2024. The first of these installments shall be paid by the last day of the calendar month of allotment and remaining monthly installment shall be paid by 15th of each month following the month of allotment. The remaining part of the license fee shall be adjusted from the 25% security amount. The balance amount from security, if any, shall be refundable after adjusting any amount due towards licensee.

Interest shall be leviable for the period of delay in depositing the license fee in accordance with the provisions of retail licensees of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor.

- (l) The minimum quota for each L-1BF Licensee shall be 75000 cases. The quota lifting schedule for L-1BF licensee shall be as under:-
 - (i) Quarter-1 Minimum 25% of annual quota
 - (ii) Quarter-2 Minimum 50% of annual quota
 - (iii) Quarter-3 Minimum 75% of annual quota
 - (iv) Quarter-4 Minimum 100% of annual quota

Provided that in case of L-1BF license allotted during the currency of policy year, the quarter-wise quota shall be calculated by dividing it equally on the number of days basis:

Provided further that the licensee shall have to lift the minimum amount of quota in the policy year. In case of failure to lift the minimum quota shall attract a penalty of ₹1800 per case. Penalty shall be leviable for deficient quantity of quota lifted at the end of each quarter calculated. However, in case any shortage of quota has been penalized in a quarter, the same deficiency of quota shall not be penalized again in any subsequent quarter(s).

- (m) The assessment fee and permit fee shall be levied as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹75 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹75 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹50 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

- (n) VAT on Imported Foreign Liquor (BIO) shall be charged at the rate of 3% with surcharge @ 5%.
- (o) The labels shall be liable to cancellation for any violation of any applicable law or breach of any provisions of excise law. A fee of ₹15,000/- shall be charged for registration of all types of Imported Foreign Liquor (BIO) brands.
- (p) A penalty of ₹3000 per bottle, irrespective of size of bottles involved, shall be imposed on every unaccounted bottle of whisky and wine found at the L-1BF premises, or at any other premises like L-1, L-2, L-2BF, L-4 & L-5, L-12C, L-12G, L-10B, L-10E etc. The penalty shall be imposed on the licensee in whose premises it is found. In case of Beer the penalty shall be ₹1500 per bottle irrespective of size of bottle.
- (q) A penalty of ₹2000 per Bottle shall be imposed on the stock of Whisky and Wine of Imported Foreign Liquor (BIO) found short at any licensed premises. In case of beer, a penalty of ₹1000 per Bottle shall be imposed.
- (r) L-1BF license shall not be located at a place which is less than five Kilometre from any custom bonded warehouse.

Any person holding a valid Import Export Certificate (IEC) and intending to (a) import IFL(BIO) directly in a Custom Bonded Warehouse situated in the State; or (b) receive consignment of IFL(BIO) from any other Custom Bonded Warehouse outside the State to its own Custom Bonded Warehouse in the State; or (c) send consignment of IFL(BIO) to any other Custom Bonded Warehouse situated within or outside the State from its own Custom Bonded Warehouse in the State; or (d) supply consignment of IFL(BIO) to any L-1BF licensee in the State from its Custom Bonded Warehouse situated within or outside the State, shall be required to register such Custom Bonded Warehouse with the department. Such person shall submit application for registration in the format specified by department alongwith a registration fee of Rs. 25,000/-. The application for registration shall be submitted in the office of Excise and Taxation Commissioner, Haryana in such manner as may be specified.

Any custom bonded warehouse established in the State and making supply of Imported Foreign Liquor (BIO) within or outside State shall be required to submit monthly information of all receipts and dispatches of liquor (for Haryana and outside) in the manner and format as prescribed by the department. Further, any custom bonded warehouse established outside the State and making supply of Imported Foreign Liquor (BIO) in Haryana shall be required to submit monthly information of such supplies to L-1BF licensees of Haryana in the manner and format as prescribed by the department. In case of non compliance, the supplies from such custom bonded warehouse shall be stopped

All consignments of IFL (BIO) issued from such Custom Bonded Warehouse must be accompanied with a copy of invoice, permit issued by Custom Authority, pass issued by Custom Authorities and a declaration to be specified by the Commissioner.

- (s) The outgoing licensee of L-1BF for the year 2022-2023 can transfer quota of unsold stock of imported foreign liquor as on 11-06-2023 to any of incoming licensees for the policy year 2023-2024. A transfer fee shall also be levied @ ₹75 per proof litre for whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin and Brandy etc., @ ₹25 per Bulk Litre for wine and @ ₹100 per Bulk litre for Beer. In addition, the licensee shall also be required to pay differential amount of assessment fee, if any.

- (t) The L-1BF licensee shall be entitled to make supplies to L-1 licensees throughout the State. The L-1 licensee will further make supplies to L-2BF licensees. The L-1BF licensees shall also be permitted to make supplies to bar licensees throughout the State.
- (u) The licensee shall install necessary fire-fighting equipment and comply with the norms of the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022, if applicable, in the approved premises.
- (v) The wholesale outlets of IFL(BIO) i.e. L-1BF licensees shall have sufficient number of CCTV cameras at entry, exit as well as in the premises with online access of live feed at district office level.
- (w) The non-compliance of provisions of this rule shall attract penal action as per law.”;
- (xiv) for clause (i-g), the following clause shall be substituted, namely :-
- “(i-g) For a license in form L-1-C Annual fee at the rates given below against each :-
- | | |
|---|--|
| (I) Whisky/ Scotch | ₹ 5,00,000 per brand |
| (II) Beer | ₹ 3,00,000 per brand |
| (III) Rum | ₹ 2,25,000 per brand |
| (IV) Gin/Vodka | ₹ 1,25,000 per brand |
| (V) Wine/Brandy/Cider/Champagne | ₹ 25,000 per brand |
| (VI) Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for supply to CSD | ₹ 30,000 per brand |
| (VII) Country Liquor | ₹ 5,00,000 per brand |
| (VIII) Ready to Drink Beverages (RTB) | ₹ 1,50,000 per brand |
| (IX) Brand label fee for exports out of State: | |
| (a) For each particular brand label of Whisky/Scotch/Rum/Gin/Vodka/ Country liquor/Beer | ₹3,00,000/- for 1st State
₹1,00,000/- for every subsequent State |
| (b) For each particular brand label Wine/Brandy/Cider/Champagne/ RTB | ₹1,50,000/- for 1st State
₹75,000/- for every subsequent State |
| (X) Brand label fee for export out of India: | |
| (a) For barands of liquor ‘Made in Haryana’ | ₹11,000/- |
| (b) Remaining brands | ₹1,00,000/- |
| (XI) Any subsequent change in any of the approved label during the year | 1/3rd of applicable fees as mentioned in this table at serial No. (i) to (x)”. |

3. In the said rules, in rule 27-A,- in sub-rule (1),-

- (i) for clauses (iii), (iv) and (v), the following clauses shall be substituted, namely:-

- “(iii) The fee for license in form L-10B obtained by the Retail licensee located in shopping malls: ₹11,00,000

Provided that the L-10B licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any L-1 Licensee in the district. The L-10B licensee shall be entitled to lift an additional quota upto 10% of Imported Foreign Liquor basic quota of his zone without payment of any additional assessment fee. Such additional quota shall be over and above the additional quota already prescribed, if any.

- (iv) the fee for license in form L-10C shall be as under:-

District	License fee
Gurugram	₹15,00,000
Faridabad, Panchkula and Sonapat	₹10,00,000
Other remaining districts	₹5,00,000:

Provided that L-10C license shall be granted for retail sale of beer to be manufactured by a Microbrewery. This license shall be granted to the holders of L-4/L-5 license.

Provided further that a security of ₹2,00,000 shall be taken from the L-10C licensees in addition to the license fee.”;

- (v) the fee for license in form L-10E shall be as under:-

District	License fee
Gurugram, Faridabad, Panchkula & Sonapat	₹4,00,000
Other districts with Municipal Corporation, Council, Committee	₹1,50,000:

Provided that in order to promote consumption of low alcoholic content drinks, a license in form L-10E shall be opened in the cities having Municipal Corporation/Municipal Council/Municipal Committee.. L-10E licenses may also be granted in Industrial Model Townships, Manesar. Also, in order to promote tourism/adventure sports tourism in the State, the case for grant of a bar license in form L-10E to any reputed hotel, resort and restaurant etc., having good infrastructure and facilities, but located beyond geographical restriction as mentioned in relevant clauses of the Excise policy, shall be considered by the Government. All such cases shall be sent by the Excise and Taxation Commissioner with his recommendation to Government for approval.

The L-10E bar licensee can remain open up to 02.00 A.M. in the State. The timings of bars may be further extended upto 08:00 A.M on payment of additional annual fee of Rs.20 Lakh per annum.

The L-10E licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹55 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹45 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹35 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

A pub licensee shall be entitled for facilities like additional points, open space, terrace, balcony etc. similar to L-4/L-5 license:

Provided that a security of ₹3,00,000 shall be taken from the L-10E licensees in addition to the license fee.”.

- (ii) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

- (vi) the fee for license in form L-10F ₹10,00,000

Provided that L-10F licenses shall be granted to those corporate offices having minimum covered area of one lakh square feet in a single premises which shall be self-owned/leased and having atleast 5000 employees. The licensee shall be allowed for possession and consumption of low alcohol content drinks (i.e. RTB, Beer, Wine) by their employees on premises. The minimum area of canteen/catery, where the license in form L-10F shall be granted in such corporate office, must not be less than two thousand square feet.

The L-10F licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees as per choice subject to the payment of assessment fee and permit fee. In case of non-availability of any BIO brands, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall allow/ensure the bar licensees to procure such BIO brands from any L-1BF licensee in the State after obtaining non-availability certificate from the

nearest two L-2BF licensees. The rates of assessment fee and permit fee for the bar licensees shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹55 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹45 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹35 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

Further, the licensed premises shall not be a thoroughfare or connected to any area frequented by public. A security of ₹3 Lakh shall be paid by the L-10F Licensee in addition to the license fee. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-10F shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

4. In the said rules, in rule 36-A-,

- (i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) The allotment of vends in rural and urban areas shall be grouped into three types of Zones, namely urban zones, rural zones and mixed zones. The Command area of a rural zone shall be the geographical area specified for establishing rural vends/sub-vends in the Zone as per Excise Arrangement. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) will be the competent authority to determine such command area as part of the Excise arrangement. Likewise, in case of mixed zone, the command area shall be the geographical area specified in the excise arrangement for establishing only rural vends/sub-vends therein. The location of vends in urban areas will be fixed in the Excise arrangement. In rural areas, the licensee shall have freedom to locate his vend(s) at any place within the command area of the Zone, subject to other provisions of excise policy/rules and approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). However, in exceptional circumstances, the Excise Commissioner (FC) can change the location of any urban vend after passing a speaking order. Similarly, in case of any rural vend or sub-vend as well, the Excise and Taxation Commissioner (FC), in exceptional circumstances, can direct to shift location of such vend/sub-vend within the command area of the zone.

The licensee shall make his own arrangement for opening of the vend(s) and sub-vend(s), with prior approval of site plan by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district. The location of all L-2/L-14A vends, sub-vends and tavern located in the district shall be mapped/geo-tagged by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned and shall be uploaded on the web portal of the Department.

The retail licences (L-2 and L-14A) shall be allotted for a period of one year i.e. from 12.06.2023 to 11.06.2024 referred hereinafter as policy year or policy year 2023-24. The policy period shall be divided into four quarters, as under:-

Quarter	Period
1st	12.06.2023 to 11.09.2023
2nd	12.09.2023 to 11. 12.2023
3rd	12.12.2023 to 11.03.2024
4th	12.03.2024 to 11.06.2024

Each quarter shall be further divided into 3 months. Each excise month will start from 12th day of the calendar month and will end on 11th day of subsequent calendar month.

Provided that if in any case the main rural vend has to be closed down due to any reason, the licensee shall shift that vend into the command area of that zone with the prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of that district.

The allotment of retail outlets of Country liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be done in units of Zones. A Zone shall comprise of two vends which shall be displayed in the excise arrangement. The zones shall be categorized as under:-

- (i) Urban Zones having two retail vends, both located in urban areas with prefixed locations;
- (ii) Rural Zones having two retail vends, both located in rural areas, with flexibility to the licensee to decide the location of these vends anywhere in his command area,

- (iii) Mixed Zones having two retail vends, with such number of vend(s) with prefixed location in urban areas as fixed in the excise arrangement and remaining vend(s) in rural area (with flexibility to the licensee to decide the location of such vend(s) anywhere in his command area) in proximity to the location of urban vend(s) of such zone. The establishment of vends shall be subject to the compliance of other provisions of the policy.

The process of allotment shall be conducted by a committee headed by the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective district as its members, in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids.

After preparation of the Excise arrangement, it shall be displayed in the office of the Deputy Commissioner of the district, office of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district, office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the district as well as office of the Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) concerned and on the departmental website www.haryanatax.gov.in and objections shall be invited by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned from the public/stakeholders for two days after the display of Excise arrangement and shall decide these objections if any within two days. The decision of the concerned Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district shall be final:

Provided that allotment of un-allotted zones of vends, the process of inviting tenders shall be continued by successively reducing the reserve price in the following manner:-

- (i) In the slabs of maximum upto 5% of the original reserve price in case reserve price of the zone is less than Rs. 5.00 crore,
- (ii) In the slabs of maximum upto 3% of the original reserve price in case reserve price of the Zone is more than Rs.5.00 crore till these are allotted or up to 4th July, 2023, or the next working day in case 4th July, 2023 happens to be a holiday, whichever is earlier. The quota of zone in such case shall be reduced. The Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) shall be the final authority to fix quota. However, the minimum reduction in quota shall be commensurate to the number of days lapsed before allotment of zone.

Provided further that in case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by maximum upto 10 % of the above mentioned original reserve price, as Excise and Taxation Commissioner(Financial Commissioner) may deem fit for this purpose and the process of inviting e-bids may be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee. The original licensee/ allottee shall be liable to make up any deficiency incurred by the State as a consequence thereof. However, in case a bid higher than the original bid is received, no benefit shall be given to the original allottee.

“(2) The allotment of retail zones of Country Liquor (L-14A) and Indian Made Foreign Liquor (L-2) vends shall be made by inviting e-tenders through a departmental portal in a completely secure and transparent manner. The detailed procedure regarding invitation of e-bids shall be finalized by the Excise and Taxation Commissioner which shall be displayed on the website of the Department www.haryanatax.gov.in. At the time of applying for registration for participation in the bid, submission of Aadhar Number and Permanent Account Number (PAN) of the applicant(s) shall be mandatory.

All allotments of licenses are subject to the approval of the Excise & Taxation Commissioner (Financial Commissioner). The Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) may reject, without assigning any reason, any allotment in public interest as the case may be, within 10 days of the date of allotment. In case no decision of Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) is conveyed within the stipulated period of ten days, the allotment shall be deemed to have been approved by the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner).

All licences, whether for wholesale or for retail sale, shall be granted subject to the provisions of the Haryana Excise Act, 1914 and the Rules/ Regulations/ Instructions/Policies framed there under from time to time as applicable to the State of Haryana.”;

- (ii) for sub-rules (4) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(4) Each bidder shall have to furnish the earnest money alongwith his bids. The Earnest Money shall be payable in the form of bank drafts only. The bank drafts shall be payable in favour of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana, Panchkula. The amount of Earnest Money shall be as under:-

Sr. No.	Reserve Price of Zone	Earnest Money
(i)	Less than ₹3 crore	₹12 .5lakh
(ii)	₹3 crore and above but less than ₹5 crore	₹25 lakh
(iii)	₹5 crore and above but less than ₹10 crore	₹50 lakh
(vi)	₹10 crore and above but less than ₹25 crore	₹75 lakh
(v)	₹25 crore and above but less than ₹40 crore	₹100 lakh
(vi)	₹40 crore and above	₹150 lakh

“(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹1,50,000/- for each Zone. The participation fee is non-refundable and non- adjustable. The participation fee shall be deposited through cash or demand draft in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district of his registration. In case of cash, a duly signed receipt shall be issued by the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .”;

- (iii) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(17) The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire annual quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located in every district in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor allocated to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Quarter	Month	Quota in percentage		
		Month-wise quota	Quarter-wise quota	Quarter-wise cumulative quota
1st	12th June, 2023 to 11th July, 2023	9%	26%	26%
	12th July, 2023 to 11th August, 2023	8%		
	12th August, 2023 to 11th September, 2023	9%		
2nd	12th September, 2023 to 11th October, 2023	7%	26%	52%
	12th October, 2023 to 11th November, 2023	9%		
	12th November, 2023 to 11th December, 2023	10%		
3rd	12th December, 2023 to 11th January, 2024	10%	27%	79%
	12th January, 2024 to 11th February, 2024	9%		
	12th February, 2024 to 11th March, 2024	8%		
4th	12th March, 2024 to 11th April, 2024	7%	21%	100%
	12th April, 2024 to 11th May, 2024	7%		
	12th May, 2024 to 11th June, 2024	7%		

The licensee shall have to lift 100% of the quota allocated to him as per the schedule described above. Failure to lift prescribed quarterly quota shall attract short quota penalty. Further, the licensee shall have to lift the unlifted quota of previous quarter in the next quarter.

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract penalty at the rate of Rs.150/-and Rs.200/-per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively for the deficient quantity.”;

- (iv) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a

recognized school/ college/main bus stand and a place of worship. Provided that in case of Urban retail liquor outlets, the Excise Commissioner can relax such distance from 150 meters to 75 meters on the recommendation of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned. Further, in urban areas, the retail liquor outlets may preferably be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the year, subsequent to the establishment of vend in the year 2023-2024.”;

- (v) for sub-rule (21), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(21) No compensation of any kind or relief in licence fee on account of natural calamity such as fire, floods, drought, earthquake etc. or on account of riots or as a result of preventive closure ordered by the District Magistrate shall be admissible to the licensee.”;

- (vi) for sub-rule (22), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(22) The Excise and Taxation Department shall facilitate setting up of the liquor vends having high revenue potential in the sites owned by Haryana Sahari Vikash Pradhikarn, Haryana State Infrastructure and Industrial Development Corporation, Metropolitan Development Authorities in the State (like GMDA, FMDA, PMDA etc.), Haryana Tourism Corporation, Urban and Rural Local Bodies etc. wherever possible. However, the rent thereof, shall be paid by the licensees directly to such Department/Corporation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall ensure the payment of rent and will send a report to Excise and Taxation Commissioner on monthly basis.”;

- (vii) for sub-rule (24) to (27), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(24) The licensee may convert one or more of his composite vends to Avant-Garde Outlet(s) in posh market or shopping mall of the urban area, where he intends to sell Indian Made Foreign Liquor only. For this purpose, some of the retail outlets in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified to be allotted as Avant-Garde Outlets. The Avant-Garde Outlets shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The Avant-Garde Outlets shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The Avant-Garde Outlets shall be entitled to lift an additional quota up to 5% of such vend’s basic quota without any levy of additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as applicable to basic quota. For the purpose of this clause, the basic quota of such vend shall be worked out by dividing the basic quota of zone with the number of vends in the zone:

The licensee shall install necessary fire-fighting equipment and comply with the norms of the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022, if applicable, in the approved premises.

Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be mandatory for all the retail licensees on demand to issue an invoice on sale. POS Machines shall be installed at sale counter of all the retail vends. Further, the licensee shall be required to adopt the integrated solution of POS prescribed by department. This provision shall also be applicable to bar licensees such as L-4/L-5, L-12C, L-12G, L-10E etc.

In case of violation of this provision, a penalty of ₹ 5000 per violation for first 10 violations, ₹10000 per violation for next 10 violations and ₹25000 per violation for next 10 violations shall be imposed on the licensee, after enquiry by the Excise Officer concerned. In case of any subsequent violation, the license shall be cancelled with forfeiture of security, after enquiry by the Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned.

It is provided further that if any retail Licensee in urban areas having license fee of his zone; (a) equal to or above ₹ 15 crore in case of Gurugram and Faridabad; (b) equal to or above ₹ 5 crore in case of remaining districts, wants to convert his vend into a Avant-Garde Outlet after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.

(25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 20% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of submitting renewal application or evaluation of e-bids, as the case may be; 5% of the license fee within seven days of the allotment or on or before 11th June, 2023 whichever is earlier; and the remaining security equal to 10% of the license fee shall be deposited by 18th of June, 2023.

In case of bids that exceed the reserve price by more than 25%, the bidder shall have to deposit an amount equal to 15% of his bid amount in addition to the amount applicable as per Earnest money deposit slabs. In case of successful bid, 15% of his bid money shall be deducted by the system and shall be deposited as 15% security.

The eighty three Percentage (83%) of his bid money/license fee shall be payable by him in monthly installments each payable by last day of each calendar month starting from the month of June, 2023 and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 83% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 17% of his bid money/license fee, shall be adjusted towards his license fee after the payment of installments amounting to 83% of his bid money/license fee. The adjustment shall be made over a period of last two months in two equal installments; each equal to 8.5 % of his bid money/license fee.

(26) The balance security equal to 3% of his bid money/ license fee shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the end of July, 2024. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. The schedule of installments shall be as under:-

Month	Installments (in terms of %age license fee)
June	8.5
July	8.5
August	8.5
September	8.5
October	8.5
November	8.5
December	9.1
January	9.1
February	9.1
March	4.7

If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, shall be forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be payable. In case, payment of installment (or part thereof) of any month is made upto 11th day of succeeding calendar month, a simple interest at the rate of 12% per annum shall be charged for the days of default on amount of late payment. However, in case default continues beyond 11th day of succeeding calendar month, a simple interest at the rate of 18% per annum shall be charged from the first day of the policy month of default.

In case any vend or vends of any zone are closed or are subsequently closed on account of falling under Covid Containment Zone, its license fee and quota shall be proportionately waived off in proportion of days of closure. For the purpose of computation of proportionate license fee and quota of a closed vend to be waived off, the license fee and quota of a zone shall be equally divided amongst all the main vends in such zone.

(27) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the policy year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 10% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be payable upto 31.03.2024 in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after February, 2024, the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) shall decide the schedule for payment of license fee and lifting of quota in such manner, as he may deem fit.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be last day of the month.”.

5. In the said rules, in rule 37, -(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The licensee shall not carry on any business connected with his license or store any liquor to be sold or otherwise dealt with under his license except in the premises specified in his license (hereinafter called the licensed premises). The Collector only in the exceptional cases, where it is impossible and impracticable to carry and store in the licensed premises large consignment of liquors, with previous sanction of Excise Commissioner may grant a permit under sub-section (3) of Section 24 of the Punjab Excise Act, 1914, to store a quantity of liquor exceeding the limit of retail sale at a place other than the licensed premises on payment of extra fee of Rs. [5,00,000] per annum. Before the grant of the permit, the collector shall satisfy himself that the proposed place is adequately guarded and that there is no means of access to it by the public. The licensee shall also install necessary fire-fighting equipment and comply with the norms of the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022, if applicable.

Further, the licensee shall install the CCTV Cameras in all the wholesale licensed premises of L-1/L-13/L-1B/L-1-B1/L-1AB/L-1AB1/L-1B1A/L-1BF and the live feed from these CCTV Cameras shall be made available to the DETC (Excise) of the district concerned. The CCTV Cameras shall also be installed at all the retail urban vends and tavern covering the relevant areas including entry, exit and the billing counters.”;

- (ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(8) No licensee can at any time advertise the sale of liquor by announcing it on loudspeakers, through social media or by any other means. All signages and advertisements of the availability of liquor shall be prohibited. The retail licensees shall maintain cleanliness and hygiene in and around the shop. Adequate number of dustbins shall be put up inside and outside the vend and Tavern. Proper lighting shall be ensured at the night time. The name of the licensee and year for which license is granted shall be displayed in Hindi and English on a board of suitable size on the face of vend as well as sub-vend by the retail licensee subject to fulfillment of all other statutory norms and instructions. Moreover, a signboard shall also be put up containing the following details:

DO NOT DRINK AND DRIVE

Name of the Licensee	
Contact number of Licensee	
License number	
Type of outlet (vend/sub-vend)	
Sub-vend serial number, if applicable	
Valid for year	
Contact number of Excise Inspector	
DETC (Ex) office contact number	
Time of opening and closing of vend	

Further, the licensee shall also display the sale price of various brands.”.

6. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV. Sub-vend shall be allowed within the command area of the Zone, subject to the prior approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). The fee per Sub-vend shall be as follows:-

Population of village	License fee per sub-vend (in Rupees)
Upto 1000	1.50 Lakh
1001-10000	3.00 Lakh
10001 and above	4.50 Lakh

For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c) and (d) mentioned below.

- (b) One sub-vend shall be allowed in a village, if the population of such village is upto 4000.

- (c) Upto two sub-vends shall be allowed in a village, if the population of such village is more than 4000 and less than 8000.
- (d) Upto three sub-vends shall be allowed in a village, if the population of such village is more than 8000.

Note:- For the purpose of this clause, "Population of Village" means population of village as per Family Information Data Repository (FIDR) established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 as on date 15.05.2023.

It is further clarified that the number of sub-vends in a particular village is allowed irrespective of count of main vend(s) in that particular village."

ASHOK KUMAR MEENA,
Excise and Taxation Commissioner, Haryana.